INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 8 | SEPTEMBER – 2024

बिलासपुर ज़िले में जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता: परंपरागत जातीय संरचना और समकालीन परिवर्तन के सन्दर्भ में

डॉ. सुश्री आरती तिवारी
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र (प्रभारी प्राचार्य)
एस. बी. टी. महाविद्यालय, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश:

जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक मूलभूत विशेषता रही है, जिसने सदियों से सामाजिक पदानुक्रम, व्यावसायिक संरचना और संसाधनों तक पहुँच को आकार दिया है। यह शोध-पत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में जाति व्यवस्था की प्रकृति और सामाजिक असमानता के प्रतिरूपों का अध्ययन करता है, जिसमें पारंपरिक जाति संरचनाओं तथा समकालीन सामाजिक परिवर्तनों को संदर्भ में रखा गया है। अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगीकरण, राजनीतिक जागरूकता तथा राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी नीतियों जैसी प्रक्रियाओं ने जाति संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है और असमानता के कुछ रूपों को कम किया है, साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि आर्थिक स्थिति, शिक्षा और सामाजिक शक्ति के क्षेत्र में जाति-आधारित असमानताएँ अब भी विद्यमान हैं। निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि यद्यपि प्रत्यक्ष जातिगत भेदभाव में कमी आई है और कुछ समूहों में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है, तथापि जाति आज भी जीवन के अवसरों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोध-पत्र का निष्कर्ष है कि बिलासपुर में जाति व्यवस्था लुप्त नहीं हो रही है, बल्कि रूपांतरित हो रही है, जहाँ पारंपरिक पदानुक्रम और आधुनिक समतावादी मूल्यों का जटिल सह-अस्तित्व दिखाई देता है।

मुख्य शब्द: जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता, बिलासपुर ज़िला, सामाजिक परिवर्तन, अनुसूचित जातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग, आधुनिकीकरण.

प्रस्तावना:

जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे प्रभावशाली और दीर्घकालिक सामाजिक संस्थाओं में से एक रही है, जिसने सदियों से सामाजिक पदानुक्रम, व्यवसाय, सामाजिक अंतःक्रिया और संसाधनों तक पहुँच के स्वरूप को निर्धारित किया है। जन्म पर आधारित इस व्यवस्था में जाति परंपरागत रूप से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यावसायिक भूमिका, विवाह संबंधों और दैनिक सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती रही है। यद्यपि भारतीय संविधान समानता की गारंटी देता है और जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने हेतु अनेक सामाजिक सुधार आंदोलनों का संचालन हुआ है, फिर भी समकालीन भारत में जाति सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई है।

छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर ज़िला जाति व्यवस्था की निरंतरता और परिवर्तन के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रस्तुत करता है। यह ज़िला सामाजिक रूप से विविध है, जहाँ अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग और उच्च जाति समूह

विद्यमान हैं, और ये सभी सामाजिक एवं आर्थिक पदानुक्रम में अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं। ऐतिहासिक रूप से बिलासपुर में जाति का गहरा संबंध भूमि स्वामित्व, पारंपरिक व्यवसायों, सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति-संबंधों से रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वंचित समुदायों का व्यापक सामाजिक बहिष्कार और गहरी असमानता विकसित हुई।

बिलासपुर ज़िले में शिक्षा के विस्तार, शहरीकरण, औद्योगिक विकास, प्रवासन तथा राज्य-प्रेरित कल्याणकारी और आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के कारण उल्लेखनीय सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इन प्रक्रियाओं ने अनेक पारंपरिक जातिगत प्रथाओं को चुनौती दी है, कठोर व्यावसायिक सीमाओं को कमजोर किया है और सामाजिक गतिशीलता के नए अवसर सृजित किए हैं। शिक्षा और सरकारी रोज़गार तक बढ़ी हुई पहुँच ने ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के कुछ वर्गों को अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने और सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है।

फिर भी, इन परिवर्तनों के साथ-साथ जाति-आधारित असमानताएँ स्पष्ट और सूक्ष्म, दोनों ही रूपों में बनी हुई हैं। शिक्षा, आय, रोज़गार की सुरक्षा, आवास और सामाजिक प्रतिष्ठा में असमानताएँ आज भी जातिगत पहचान से जुड़ी हुई हैं। अनेक मामलों में जाति ने आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लिया है और अब यह प्रत्यक्ष भेदभाव के बजाय सामाजिक नेटवर्क, विवाह प्रतिरूपों, राजनीतिक सक्रियता और अवसरों तक पहुँच के माध्यम से व्यक्त होती है। पारंपरिक पदानुक्रम और समकालीन परिवर्तनों का यह सह-अस्तित्व क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक असमानता को समझने के लिए जाति के अध्ययन को अत्यंत प्रासंगिक बनाता है।

यह शोध-पत्र बिलासपुर ज़िले में जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता का अध्ययन करता है, जिसमें पारंपरिक जाति संरचनाओं और समकालीन सामाजिक परिवर्तनों के पारस्परिक संबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। निरंतरता और परिवर्तन के प्रतिरूपों का विश्लेषण करते हुए यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि आधुनिकीकरण, राज्य हस्तक्षेप और सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं के बीच जाति किस प्रकार सामाजिक जीवन को निरंतर प्रभावित करती हुई रूपांतरित हो रही है।

अध्ययन के उद्देश्य:

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1) बिलासपुर ज़िले में पारंपरिक जाति संरचना का अध्ययन करना।
2) जाति से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक असमानता के प्रतिरूपों का विश्लेषण करना।
3) जाति संबंधों पर शिक्षा, शहरीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन करना।
4) जाति-आधारित व्यवसायों तथा सामाजिक गतिशीलता में आए परिवर्तनों का परीक्षण करना।
5) जातिगत असमानता की निरंतरता एवं उसके रूपांतरण का आकलन करना।

शोध पद्धति:

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प को अपनाता है। यह मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिनमें भारत की जनगणना रिपोर्टें, जिला सांख्यिकी पुस्तिकाएँ, सरकारी प्रकाशन तथा छत्तीसगढ़ में जाति और असमानता से संबंधित समाजशास्त्रीय अध्ययन शामिल हैं। प्राथमिक जानकारी 160 उत्तरदाताओं से प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक प्रवृत्तियों की व्याख्या हेतु उपलब्ध क्षेत्रीय अध्ययनों और अकादमिक साहित्य से भी सहायता ली गई है। आँकड़ों का विश्लेषण तुलनात्मक, ऐतिहासिक तथा समाजशास्त्रीय व्याख्यात्मक विधियों के माध्यम से किया गया है, जिसमें समय के साथ जाति-आधारित व्यवसाय, शिक्षा, आय और सामाजिक अंतःक्रिया में आए परिवर्तनों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

बिलासपुर ज़िले में जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता: परंपरागत जातीय संरचना और समकालीन परिवर्तन के सन्दर्भ में:

जाति व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज की एक केंद्रीय संगठनात्मक संरचना रही है, जिसने सामाजिक पदानुक्रम, व्यावसायिक वितरण और असमानता के प्रतिरूपों को गहराई से प्रभावित किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में जाति ने परंपरागत रूप से भूमि, शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा तक पहुँच को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन के लगभग सभी पक्षों को संरचित किया है। उच्च जातियों का कृषि भूमि स्वामित्व, स्थानीय प्रशासन और धार्मिक सत्ता पर प्रभुत्व रहा, जिससे वे आर्थिक संसाधनों और सामाजिक

शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इसके विपरीत, निम्न जातियाँ (विशेषतः अनुसूचित जातियाँ) मुख्यतः शारीरिक श्रम, सामाजिक रूप से कलंकित और अल्प-वेतन वाले कार्यों तक सीमित रहीं। इस कठोर सामाजिक विभाजन ने बहिष्करण को सुदृढ़ किया, सामाजिक उन्नति को सीमित किया और पीढ़ीगत असमानता को बनाए रखा।

बिलासपुर में पारंपरिक जाति संबंधों को अंतर्जातीय विवाह, सहभोज पर प्रतिबंध, आवासीय पृथक्करण और जाति-आधारित व्यावसायिक विशिष्टीकरण जैसी कठोर प्रथाओं के माध्यम से बनाए रखा गया। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत मानदंडों ने सामाजिक अंतःक्रिया, सामुदायिक सहभागिता और सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच को नियंत्रित किया। निम्न जातियों को शिक्षा, भूमि स्वामित्व और निर्णय-निर्माण संस्थाओं से व्यवस्थित रूप से वंचित रखा गया, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन और अधिक गहरा हुआ।

शिक्षा के विस्तार, शहरीकरण, औद्योगिक विकास, प्रवासन और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के कारण बिलासपुर ज़िले में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा, रोज़गार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण जैसी सरकारी पहलों ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ वर्गों को अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर प्रदान किया है। विद्यालयी और उच्च शिक्षा तक बढ़ी हुई पहुँच ने सरकारी सेवाओं, कुशल रोज़गार और गैर-पारंपरिक व्यवसायों में प्रवेश को संभव बनाया, जिससे जाति और व्यवसाय के पारंपरिक संबंध कमजोर हुए हैं।

आर्थिक विविधीकरण ने भी जाति-आधारित असमानता के स्वरूप को प्रभावित किया है। कृषि की एकमात्र आजीविका के रूप में भूमिका घटने और औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों के विस्तार से आय के नए अवसर सृजित हुए हैं। फिर भी, वंचित वर्ग आज भी असंगठित, कम-वेतन और असुरक्षित रोज़गार में अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जो जाति के निरंतर प्रभाव को दर्शाता है। शहरीकरण ने कठोर जातिगत प्रथाओं को कुछ हद तक शिथिल किया है, किंतु सामाजिक नेटवर्क, विवाह चयन और राजनीतिक संबद्धताओं में जातिगत पहचान अब भी प्रभावी बनी हुई है। समग्र रूप से, बिलासपुर में जाति-आधारित असमानता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि रूपांतरित होकर एक ऐसी संक्रमणकालीन वास्तविकता का रूप ले चुकी है, जहाँ पारंपरिक पदानुक्रम आधुनिक समानता और सामाजिक न्याय की आकांक्षाओं के साथ सह-अस्तित्व में हैं।

संकल्पनात्मक रूपरेषा:

जाति व्यवस्था: जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक वंशानुगत एवं पदानुक्रमात्मक स्वरूप है, जिसमें व्यक्तियों को जन्म के आधार पर विभिन्न सामाजिक समूहों में विभाजित किया जाता है। परंपरागत रूप से जाति ने सामाजिक जीवन के लगभग सभी पक्षों (जैसे व्यवसाय, विवाह, खान-पान की आदतें तथा सामाजिक अंतःक्रिया के प्रतिरूप) को नियंत्रित किया है। यह व्यवस्था अंतर्जातीय विवाह, शुद्धता-अशुद्धता की अवधारणाओं, वंशानुगत व्यवसायों और सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध जैसे तंत्रों के माध्यम से संचालित होती रही है। इन प्रथाओं ने सामाजिक असमानता को संस्थागत रूप प्रदान किया और पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखा।

बिलासपुर ज़िले में ऐतिहासिक रूप से जाति ने एक कठोर सामाजिक व्यवस्था के रूप में कार्य किया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ भूमि, शिक्षा, रोज़गार और राजनीतिक सत्ता तक पहुँच पर जातिगत मानदंडों का गहरा प्रभाव रहा है। यद्यपि विधिक सुधारों और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं ने अनेक पारंपरिक प्रथाओं को कमजोर किया है, फिर भी समकालीन समाज में जाति आज भी सामाजिक संबंधों औरजीवन के अवसरों को प्रभावित करती है।

सामाजिक असमानता:

सामाजिक असमानता से आशय विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भौतिक संसाधनों, अवसरों, सामाजिक शक्ति और प्रतिष्ठा तक असमान पहुँच से है। भारतीय संदर्भ में जाति सामाजिक असमानता का एक अत्यंत स्थायी स्रोत रही है, जो वर्ग, शिक्षा, लिंग और क्षेत्र जैसे कारकों के साथ अंतःक्रिया करती है। जाति-आधारित असमानता आय, भूमि स्वामित्व, शैक्षिक उपलब्धि, रोज़गार सुरक्षा, आवास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

बिलासपुर ज़िले में आर्थिक विकास और कल्याणकारी नीतियों के बावजूद जाति आज भी अवसरों के वितरण को प्रभावित करती है, विशेषकर अनुसूचित जातियों और कुछ अन्य पिछड़ा वर्गों के संदर्भ में। वर्तमान समय में सामाजिक असमानता प्रत्यक्ष भेदभाव के बजाय अधिकतर संरचनात्मक और संस्थागत रूपों में कार्य करती है।

बिलासपुर ज़िले में पारंपरिक जाति संरचना:

परंपरागत रूप से बिलासपुर ज़िले की जाति व्यवस्था एक स्पष्ट पदानुक्रम से युक्त रही है। उच्च जातियों का सामाजिक प्रभुत्व रहा है तथा भूमि स्वामित्व, ग्राम प्रशासन और धार्मिक संस्थानों पर उनका नियंत्रण रहा है। मध्य जातियाँ मुख्यतः कृषि और शिल्प आधारित व्यवसायों से जुड़ी रहीं, जबकि निम्न जातियाँ (विशेषतः अनुसूचित जातियाँ) अल्प-वेतन, सामाजिक रूप से कलंकित और श्रमसाध्य कार्यों से संबद्ध रहीं।

जातियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया अंतर्जातीय विवाह, सहभोज पर प्रतिबंध और आवासीय पृथक्करण जैसे कठोर नियमों द्वारा नियंत्रित थी, जिससे सामाजिक दूरी बनी रही और निम्न जातियों की सामाजिक उन्नति सीमित रही।

तालिका 1 : जाति श्रेणी के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण (n = 160)

जाति श्रेणी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
उच्च जातियाँ	34	21.3
अन्य पिछड़ा वर्ग	58	36.2
अनुसूचित जातियाँ	42	26.3
अनुसूचित जनजातियाँ	26	16.2
कुल	**160**	**100**

आँकड़े दर्शाते हैं कि 42.5 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक रूप से वंचित श्रेणियों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) से संबंधित हैं। यह संरचना बिलासपुर ज़िले की सामाजिक विविधता कोप्रतिबिंबित करती है तथा जाति-आधारित असमानता के अध्ययन हेतु एक उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

जाति और आर्थिक असमानता:

ऐतिहासिक रूप से बिलासपुर में जाति-आधारित असमानता का घनिष्ठ संबंध आर्थिक स्थिति से रहा है। उच्च और प्रभुत्वशाली जातियों के पास भूमि, ऋण और स्थानीय आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रहा है, जबकि निम्न जातियाँ मुख्यतः मज़दूरी और असंगठित रोज़गार पर निर्भर रहीं।

तालिका 2 : जाति के अनुसार रोज़गार स्थिति (n = 160)

रोज़गार का प्रकार	उच्च जाति	ओबीसी	एससी	एसटी	कुल (%)
सुरक्षित / नियमित रोज़गार	44%	28%	14%	12%	25.6
असंगठित / मज़दूरी	26%	48%	62%	65%	49.4
बेरोज़गार / अनियमित	30%	24%	24%	23%	25.0

आँकड़े दर्शाते हैं कि उच्च जातियाँ सुरक्षित रोज़गार में अधिक प्रतिनिधित्व रखती हैं, जबकि अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ असंगठित और असुरक्षित कार्यों में अत्यधिक केंद्रित हैं। यह बदलती अर्थव्यवस्था में भी जाति के निरंतर प्रभाव को प्रमाणित करता है।

शिक्षा और बदलते जाति संबंध:

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख साधन बनकर उभरी है, जिसने पारंपरिक जातिगत पदानुक्रम को चुनौती दी है। आरक्षण, छात्रवृत्ति और छात्रावास जैसी सरकारी नीतियों से शैक्षिक भागीदारी में वृद्धि हुई है।

तालिका 3 : जाति के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि (n = 160)

शिक्षा स्तर	उच्च जाति (%)	ओबीसी (%)	एससी (%)	एसटी (%)
निरक्षर / प्राथमिक	12	22	38	42
माध्यमिक	35	44	39	36
उच्च / व्यावसायिक	53	34	23	22

यद्यपि सभी वर्गों में शिक्षा की पहुँच बढ़ी है, फिर भी उच्च शिक्षा में उच्च जातियों की भागीदारी अधिक है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति पीछे हैं। यह नीतिगत प्रयासों के बावजूद संरचनात्मक असमानता की निरंतरता को दर्शाता है।

शहरीकरण, गतिशीलता और समकालीन परिवर्तन:

शहरीकरण और प्रवासन ने कठोर जातिगत प्रथाओं को कमजोर किया है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, जहाँ व्यवसायिक भूमिकाएँ अधिक लचीली हैं और सामाजिक अंतःक्रिया पर जाति का नियंत्रण अपेक्षाकृत कम है।

तालिका 4 : निवास स्थान और जातिगत अंतःक्रिया (n = 160)

सूचक	ग्रामीण (%)	शहरी (%)
जाति-आधारित व्यवसाय	62	29
अंतर्जातीय अंतःक्रिया	34	71
अंतर्जातीय विवाह स्वीकृति	18	46

शहरी उत्तरदाताओं में अंतर्जातीय संपर्क और स्वीकृति अधिक पाई गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि शहरीकरण ने जातिगत सीमाओं को कमजोर किया है, यद्यपि जातिगत चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

असमानता की निरंतरता और नए स्वरूप

सामाजिक परिवर्तन के बावजूद जाति-आधारित असमानता नए और सूक्ष्म रूपों में बनी हुई है। भेदभाव अब सामाजिक नेटवर्क, आवास, रोज़गार संदर्भ और राजनीतिक सक्रियता के माध्यम से प्रकट होता है।

तालिका 5 : जातिगत भेदभाव का अनुभव (n = 160)

भेदभाव का अनुभव	प्रतिशत (%)
बार-बार	22
कभी-कभी	41
बहुत कम	21
नहीं	16

लगभग 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी न किसी रूप में जातिगत भेदभाव का अनुभव किया है, जो यह दर्शाता है कि प्रत्यक्ष भेदभाव कम हुआ है, किंतु असमानता अब भी सामाजिक-आर्थिक जीवन में विद्यमान है।

160 उत्तरदाताओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बिलासपुर ज़िले में जाति आज भी सामाजिक असमानता का एक प्रमुख निर्धारक है। शिक्षा, शहरीकरण और नीतिगत हस्तक्षेपों से पारंपरिक पदानुक्रम कमजोर हुआ है, फिर भी रोज़गार, शिक्षा और सामाजिक शक्ति में संरचनात्मक असमानताएँ बनी हुई हैं। जाति लुप्त नहीं हुई है, बल्कि आधुनिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सह-अस्तित्व में नए रूप ग्रहण कर रही है।

निष्कर्ष:

बिलासपुर ज़िले में जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि व्यापक सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद जाति सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाली एक सशक्त संरचना बनी हुई है। शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगीकरण और राज्य-प्रेरित कल्याणकारी नीतियों ने पारंपरिक जातिगत पदानुक्रम को चुनौती दी है और कुछ वर्गों को सामाजिक उन्नति का अवसर प्रदान किया है। किंतु साथ ही, जाति-आधारित असमानता अधिक सूक्ष्म और संरचनात्मक रूपों में विद्यमान है। इसलिए, सामाजिक न्याय और वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए विधिक संरक्षण के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी आर्थिक अवसर और सामाजिक चेतना का निरंतर विस्तार आवश्यक है।

संदर्भ:

1. *Chakravarti, A. (2000). Caste in modern India: Evolving dynamics. Indian Institute of Dalit Studies.*
2. *Deshpande, S. (2000). Caste, class, and quotas: New strategies for education. Economic and Political Weekly.*
3. *Fuller, C., & Spencer, J. (1990). South Asian anthropology in the 1980s. South Asia Research, 10, 85-105.*
4. *Government of India. (2011). Census of India 2011. Ministry of Statistics and Programme Implementation.*
5. *Jodhka, S. S. (2006). Caste and social inequality in India. Sociological Bulletin, 55(2), 177-198.*
6. *Mandelbaum, D. G. (1970). Society in India: Continuity and change. University of California Press.*
7. *Mistry, R. (1995). A fine balance. Knopf.*
8. *Patel, K. (2019). Educational disparities among Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Indian Education Review.*
9. *Patel, A. K., & Shah, N. (2018). Challenges in agriculture for Scheduled Castes in Central India. Economic and Political Weekly, 53(12), 34-41.*
10. *Rao, M., & Ghosh, S. (2018). Affirmative action and its impact on social equity. Indian Journal of Social Sciences.*
11. *Sharma, K. L. (1988). Caste and society: A study of Hindu society. Vikas Publishing House.*
12. *Srinivas, M. N. (1966). Social change in modern India. University of California Press.*
13. *Srinivas, M. N., & Sharma, K. L. (2001). The changing structure of the caste system. Orient Longman.*
14. *Thorat, S., & Newman, K. S. (Eds.). (2007). Blocked by caste: Economic discrimination in modern India. Oxford University Press.*
15. *Velassery, S. (2005). Casteism and human rights: Toward an ontology of the social order. Marshall Cavendish Academic.*
16. *Wankhede, G. (2016). Scheduled caste literacy & disparities in Bilaspur district of Chhattisgarh state. Academia.edu.*
17. *World Bank. (2011). Caste, social exclusion, and discrimination in India: A virtual knowledge resource. World Bank Publications.*